1	2	3
मुरादाबाद	मुरादाबाद	कार्पोरेशन बैंक
कानपुर	किदवई रोड	-तदैव-
झांसी	टेशनरोड	पी०एन०बी०
मुरादाबाद	मजोला दिल्ली रोड	-तदैव-
जौनपुर	शंकर मंडी	-तदैव-
गाजियाबाद, हापुर	सुरजपूर-कासनाः औद्य० क्षेत्र	यूनियन बैंक आफ इंडिया

गुजरात में जीवन बीमा निगम की शाखायें

6410. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्लः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 अक्तूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कार्यरत जीवन बीमा निगम की शाखाओं की संख्या का सर्कल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा सर्कल-वार तथा शाखा-वार कितनी-कितनी धनराशि अर्जित की गई तथा क्या सेवायें प्रदान की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निगम द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया तथा पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार द्वारा गुजरात के लोगों को बीमा योजना के अधीन लाने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) गुजरात में जीवन बीमा निगम की प्रभाग-वार शाखाओं की संख्या निम्नलिखित हैः

प्रभाग	शाखाओं की संख्या
अहमदाबाद	29
गांधीनगर	25
बडोदरा	16
राजकोट	18
भावनगर	10
सूरत	21
नाडियाड	17
	136

(ख) और (ग) जीवन बीमा कारोबार में लाभों की कोई प्रणाली नहीं होती। फिर भी समूचे निगम को परिसम्पत्तियों और देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा अधिशेष का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के अधिशेष का 95 प्रतिशत भाग पालिसी धारकों में बांट दिया जाता है और 5 प्रतिशत भाग सरकार को अदा किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात के नाडियाड को छोड़कर जो 1993-94 में ही बना है, छः प्रभागों में प्रभाग-वार और शाखा-वार किए गए कारोबार का ब्यौरा तथा उस अवधि के दौरान निगम द्वारा निवेशित धनराशि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र में 132] गुजरात सहित सभी राज्यों में स्वीकृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अपना कारोबार और निवेश बढ़ाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा सतत प्रयास किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Disposal of Complaints by SEBI

6411. SHRI ISH DUTT YADAV:
CHAUDHARY HARMOHAN SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the complaints sent to SEBI and Stock Exchange are not disposed of effectively and immediately by the Registrar Office;

(b) if so, what is Government's reaction;

(c) the number of complaints received every year in SEBI and Stock Exchange during the last three years; and

(d) the number of complaints disposed of during the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE

MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Huge Surplus on Capital Accounts

6412. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the gap between capital receipts and capital expenditure has widened recently, resulting in a huge surplus on capital account;

(b) if so, capital surplus during 1992-93 (B.E.) and 1993-94 (B.E.);

(c) how these figures compare with that of 1960-61, 1970,71 and 1980-81; and

(d) what are the reasons for not utilising money available in the capital account?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Capital receipts comprise (i) non-debt receipts like recoveries of loans, disinvestment etc., and (ii) borrowings from isue of 91 day treasury bills and other sources. The details of capital receipts excluding 91 day treasury bills are as under:

(Rs. Crores)

	1960-61 Actuals	1970-71 Actuals	1980-81 Actuals	1992-93 BE	1993-94 BE
Capital receipts	980	1907	7963	38010	42800
Capital expanditure	863	2280	8737	29517	29484

(d) In 1960-61 the suprlus Capital receipts were used to reduce Treasury Bills debt and in 1992-93 BE and 1993-94 BE they were used to meet part of revenue deficits of those years. In 1970-71 the deficit in capital account was met partly by revenue surplus and partly by 91-days Treasury Bills and the deficit in 1980-81 was met by Treasury Bills.

Increase in Bank Service Charges

6413. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to hike the Bank service charges on Bank accounts in the New Financial Year 1994-95;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the quality of Banking service needs to be improved to justify any increase in service charges;

(d) whether Government have received representations for reduction in service charges; and

(e) if so, the steps/measures taken or to be taken by the Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) No proposal is under consideration of the Government for increasing the service charges of public sector banks. However, certain proposals for levying differential service charges keeping in view customer profile, degree of computerisation and volume of business are under consideration of the Indian Banks' Association (IBA).

(c) With a view to improving the